nanagar, Agartala, Tripura against the Editor, The Syandan Patrika, Agartala, Tripura.

(5) Complaint of Shri Sayeedullah Mongrum, M.L.A., General Secretary, The Shillong Muslim Union, Bishnupur, Shillong against the Editor, Agardoot, Assamese Bi-Weekly, Dispur Gauhati.

(6) Complaint of Shri T. C. K. Lotha, Chief Secretary to Govt. of Nagaland, Kohima against Nagaland Post.

(7) Complaint of Shri T. C. K. Lotha, Chief Secretary to Govt. of Nagaland, against Hill Express.

(8) Complaint of Shri T. C. K. Lotha, Chief Secretary to Govt. of Nagaland against the Nagaland Journal.

(9) Complaint of Shri Sudhir Rangan, M.P. (Rajya Sabha), N. Delhi against the Editor, Dainik Desher Katha, Agartala.

(10) Shri Bidhan Purkayastha, Editor, Cachar Times(Silchar, Assam against the Editor, Sonar Cachar, Assamese Daily Silchar.

(11) Complaint of Shri Atul C. Marak, Hon'ble GAD Minister, Govt of Meghalaya, Distt. W. Gargo Hills, Meghalaya against the Editor, The Meghalaya Gaurdian, Shillong.

Criteria for approval of serials

7873 SHRI T. VENKATRAM REDDY: Will the Minister of INFORMATION & BROADCASTING be pleased to state:

(a) the criteria laid down for the approval of Doordarshan serials;

(b) whether there is any serial Review Committee to review the rejected serials;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the number of serials which were rejected at first but were later accepted when resubmitted to the Serial Review Committee during 1993 and 1994?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. P. SINGH DEO): (a) The broad selection criteria for serials are as follows:

(i) Story-line and its contemporary relevance;

((ii) Treatment of theme;

(iii) Overall competence of the technical crew; and

(iv) relevance to Doordarshan's programme requirements.

(b) and (c) Yes, Sir. The guidelines under Doordarshan's New Sponsorship Scheme provided for the appeals of producers whose proposals had been rejected being examined by a review committee consisting of the Director General, Doordarshan and at least three non-official experts (other than the non-official experts who had considered the proposal earlier) from the penal maintained by Doordarshan.

(d) Doordarshan did not receive an appeal for reconsideration of any of the 3095 proposals rejected by the Selection Committee under the said scheme.

Counter-guarantee in Dhabol Power Project

7874. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the World Bank was not in favour of giving counter-guarantee to foreign private investor in Dabhol project in Maharashtra;

(b) if so, the reasons for going against the wishes of the World Bank and its reaction thereon;

(c) whether Government propose to invite fresh bids for Phase-II of that project to bring down its cost; and

(d) if so, the stage of consideration of the entire project?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILA BEN CHIMANBHAI PATEL): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) It is for Government of Maharashtra to take a suitable decision in this matter.

(d) Does not arise.

बिहार में विद्युत संकट

7875. **श्री आस मोहम्मद : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में विद्युत संकट बढ़ता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल) : (क) वर्ष 1994-95 के दौरान बिहार में ऊर्जा की आवश्यकता 9410 मिलियन यूनिट थी, जबकि इसकी तुलना में उपलब्धता 6295 मिलियन यूनिट थी, जो उसी अवधि के दौरान 7.1 की अखिल भारतीय औसत कमी की तुलना में 33.1% की कमी को द्योतक है ।

(ख) बिहार विद्युत की उपलब्धता की तुलना में विद्युत की मांग अधिक होने के कारण विद्युत की कमी का सामना कर रहा है ।

(ग) मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को समाप्त करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं, नई विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना, अल्प अवधि में निर्माण की जाने वाली परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना, विद्यमान विद्युत स्टेशनों के कार्य निष्पादन में सुधार करना पारेषण एवं वितरण संबंधी हानियों की मात्रा को कम करना, बेहतर मांग प्रबंध और ऊर्जा संवर्धन उपायों को क्रियान्वित करना और पड़ोसी राज्यों/प्रणालियों से ऊर्जा के अंतरण की व्यवस्था करना आठवीं योजना अवधि के दौरान बिहार में 476.5 मेगावाट की क्षमता जोड़े जाने की परिकल्पना की गई है । इसके अलावा, पूर्वी क्षेत्र में अधिष्ठापित किए जा रहे केन्द्रीय क्षेत्र के केन्द्रों से भी राज्य अपने समुचित हिस्से की विद्युत प्राप्त करेगा ।

गुजरात में गैर-सरकारी क्षेत्र के विद्युत संयंत्रों का प्रस्ताव

7876. **श्री संघ प्रिय गौतम : क्या** विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में गैरसरकारी क्षेत्र से गैस आधारित, लिग्नाइट और ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने के संबंध में वर्षवार कितने प्रस्ताव/आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) उस राज्य में किन-किन स्थानों पर कितनी-कितनी क्षमता का संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है और उनमें अन्तर्ग्रस्त गैरसरकारी कम्पनियों के नाम क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इन आवेदनों/प्रस्तावों को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है ;

(घ) प्रत्येक संयंत्र की अनुमानित लागत कितनी है और क्या इन गैर-सरकारी क्षेत्र के संगठनों ने प्रस्तावित